RAJYA SABHA

Tuesday, the 9th May, 2000/19 Vaisakha, 1922 (Saka)

The House met at Eleven of the clock. **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*601 [The questioners (Shri Sukhdev Singh Libra and Sardar Gurcharan Singh Tohra) were absent. For answer *vide* page 27 *infra.*]

MR. CHAIRMAN: Question No. 602. Shri Parmeshwar Kumar Agarwalla

Progress of National Highway Development Programme

*602. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the work on Phase-I of National Highway Development Programme has been completed;

(b) if so, what is the status of Phase-II; and

(c) what are the targets fixed for the Phase II?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJNATH SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of Rajya Sabha.

Statement

(a) to (c) Work on National Highway Development Programme (NHDP) has not been divided into phases. NHDP consists of 4/6-laning of the Golden Quadrilateral and North-South and East-West Corridors. Work on Golden Quadrilateral is scheduled to be completed by 2003 and on the corridors by 2009.

Total length covered under NHDP

Golden Quadrilateral	: 5952 Km.
North-South and East-West Corridors	: 7300 Km.
TOTAL:	**13252 Km.**

On the Golden Quadrilateral 558 Km. has already been four-laned and work on 712 Km. is under progress.

On the North-South and East-West Corridors 630 Km. is already four-laned and work on 272 Km. is under progress.

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवालाः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और भूतल परिवहन मंत्री श्री राजनाथ सिंह को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं कि राष्ट्र की इस वृहत योजना को उन्होंने कार्यान्वित करने का संकल्प किया है। 52,000 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग के चौड़ाकरण एवं इसको मजबूत करने की योजना है। इस पर राष्ट्र का एक लाख 9 हजार करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इस संदर्भ में जो उत्तर प्राप्त हुआ है, इसके संबंध में मेरा पहला प्रश्न था कि किस फेज में डेवलमेंट का काम पूरा हुआ है तो उन्होंने कहा कि कोई फेजवाइज डेवलपमेंट का काम नहीं है। मेरे पास जो आंकड़ें हैं उनके हिसाब से यह जो डेवलपमेंट का काम है यह 13252 किलोमीटर अलग-अलग मदों में करीब 58 हजार करोड़ रुपये का खर्चा होने वाला था। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या इस काम के लिए वित्तीय उपलब्धता की कोई कठिनाई है और यदि है तो आप उसके समाधान के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? यह प्रश्न का 'क' भाग है।

मेरे प्रश्न का 'ख' भाग यह है कि इसकी अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता होनी चाहिए तो इसकी गुणवत्ता के संबंध में गारंटी प्राप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है? सरकार कैसे देखती है कि गुणवत्ता के अनुसार पूरा काम ठीक से हो रहा है?

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो उन्होने 52 हजार किलोमीटर के राजमार्ग की चर्चा की है, वह 52 हजार किलोमीटर तो हमारे देश के पूरे नेशनल हाईवे की लम्बाई है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वह केवल नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जो 13252 किलोमीटर की सड़क आती है उसके डेवलपमेंट के बारे में पूछा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे डेवपलमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हमारी दो योजनाएं हैं—एक तो गोल्डन क्वाड्रीलेटरल स्कीम है और दूसरी कॉरीडोर स्कीम है यानी नार्थ को साउथ से और ईस्ट को वेस्ट से जोड़ने की स्कीम है। हमने इस कार्यक्रम को फेजिज के अन्तर्गत नहीं लिया है। गोल्डन क्वाड्रीलेटरल स्कीम के अन्तर्गत लगभग 5952 किलोमीटर की सड़क आती है यानी राजधानी को कलकत्ता, मुम्बई और चेन्नई से 5952 किलोमीटर के मार्ग द्वारा जोड़ने की योजना है। हमने प्राइवेटाइजेशन स्टडीज का

काम पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त इस गोल्डन क्वाड्रीलेटरल स्कीम के अन्तर्गत आने वाली 558 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो गया है और 712 किलोमीटर सड़क का कार्य अंडर इम्पलीमेंटशन में है। कॉरीडोर में 630 किलोमीटर की सड़क का काम पूरा हो चुका है और 270 किलोमीटर की सड़क अंडर इम्पलीमेंटेशन में है यानी उसका कांट्रेक्ट अवार्ड किया जा चुका है। जहां तक वित्तीय कठिनाई का सवाल है मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी प्रकार का कोई वित्तीय संकट नहीं होने पाएगा और हम आगे इस पूरी योजना को कैसे अंजाम देंगे अथवा इस कार्यक्रम को कैसे पूरा कर लेगें, इसके लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कैसे होगी, इसके संबंध में एक कंप्रिहेंसिव थिंकिंग हमारे यहां हो चुकी है। यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे कि वह व्यवस्था हम कैसे करेंगे तो मैं उसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवालाः माननीय सभापति महोदय, योजना के संबंध में मेरे पास जो आंकड़े हैं, प्रथम चरण में 1848 किलोमीटर का काम लिया गया है जिसमें कहा गया है कि यह काम 2003 से लेकर 2009 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर तक की एक सड़क बनी है, उस सड़क के दोनों तरफ स्तर अलग-अलग हैं — जाने वाली सड़क की ऊंचाई अलग है और आने वाली सड़क की ऊंचाई अलग है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी तकनीकी कारण से यह स्तर अलग-अलग रखा गया है? क्योंकि स्तर अलग-अलग करने से खर्चे भी बढ़ेंगे और किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इससे ऐक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसा किन कारणों से किया गया है? इसके अतिरिक्त जो दिल्ली से जयपुर जाने वाली सड़क है, यदि आप पता करें तो कई स्थानों पर उसकी व्यवस्था बहुत खराब है। मेरा प्रश्न है कि इसकी गुणवत्ता को देखने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? उसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि गोल्डन क्वाड्रीलेटरल स्कीम के अंतर्गत जिन सड़कों का हम निर्माण कर रहे हैं, फोर लेन की सड़कों का, यह काम 2003 तक पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कॉरीडोर हम बना रहे हैं—नॉर्थ-साउथ, ईस्ट-वैस्ट कॉरीडोर — यह काम 2009 तक पूरा हो जाएगा। वैसे हमारा प्रयास है कि हम 2009 से पहले यानी 2007 तक इस काम को पूरा कर दें लेकिन जिस स्पैसिफिक स्ट्रैच के बारे में उन्होंने कहा है — दिल्ली जयपुर सड़क के बारे में, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि सड़क का निर्माण ऐसा नहीं होगा कि दो-तीन एजेंसियों के द्वारा उसे बनाया जाए। उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आने पाएगा क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत जिन सड़कों का हम निर्माण कर रहे हैं, उसमें हम ग्लोबल टैंडर इनवाइट करते हैं और वह ग्लोबल टैंडर हम इसलिए इनवाइट करते हैं कि किसी भी प्रकार से उसकी क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में कोई कमी न आने पाए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister has pointed out in reply to the first supplementary of the question that he is in a position to give detailed information about the financial support which the project will have. I would like to know from him about the financial support which the project will have. In order to complete the Golden Quadrilateral by 2003, what would be the requirement and what has been the Budget allotment for the current year? And in order to complete the Corridor by 2009, what would be that total requirement and how much has he got? Has he received it on pro rata basis? But in this connection, I would also like to know from him one thing. When we construct a road, sometimes, with the help of global tenders, having the updated latest technology, we construct a good road. But the problem comes thereafter. For instance, when I travel by the link road of NH-2, the national highway No. 2 to the national highway No. 31, I find that a first class road which was created a couple of years ago, has started deteriorating for want of maintenance. You can create a first class road, a Corridor or a Golden Quadrilateral, but as per the existing arrangements, the maintenance of the national highways is with the State Governments. All these projects are not new. It is the expansion of the national highways to four lanes or six lanes. Therefore, as per the old arrangement, the maintenance will continue to be with the State Governments, and invariably, we find that the State Governments do not have the resources and they always make the complaint about shortage of resources and whatever good road you may initially construct or expand or widen, in the course of a few years, it comes back to almost nothing but a conglomeration of the spot. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is contemplating to provide more funds for the maintenance of these roads. They are entirely bearing the expenses of construction and expansion of four lanes and six lanes. For the maintenance of the national highways also, the funds go from the Centre to the States. But there is always a complaint about the inadequacy of funds to maintain the good roads which are being initially constructed. I would like to know whether any adequate financial backing arrangement will be construed to maintain their standards, especially for the Corridor roads and the Golden Quadrilateral.

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, यह मूल प्रश्न तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है लेकिन माननीय प्रणब मुखर्जी ने नेशनल हाईवे की सड़कों के अपग्रेडेशन और उनकी हालत के संबंध में भी जानकारी चाही है। तो यह सच है कि 13000 किलोमीटर के अतिरिक्त लगभग 40000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़कें सारे देश भर में हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि इन 40000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। आवश्यकता है उनको अपग्रेड करने की, आवश्यकता है उनको डेवलप करने की। इसलिए हमने एक योजना बनाई है कि आगामी दो वर्षों के अंदर इस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अतिरिक्त जो नेशनल हाईवे की लगभग 40000 किलोमीटर की सड़कें हैं, उनकी हालत में हम बहुत अधिक सुधार भले ही न कर पाएं लेकिन उन सड़कों को हम राइडिंग क्वालिटी की निश्चित रूप से दो वर्षों में बना देंगे, ऐसा मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: What about the money? How much money have you got this year for these two projects—the Golden Quadrilateral and the East-West Corridors? ...*(Interruptions)*... For the Corridors project, how much money you have got in the current financial year; that I wanted to know. Give me the break-up.

SHRI RAJNATH SINGH: Under the Goplden Quadrilateral project, the length covered is 270 kms. at a cost of Rs. 876 crores. यह वर्ष 1999-2000 के लिए एक्सपेंडिचर है जो गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल स्कीम के अंतर्गत होगा, इसकी जानकारी मैं दे रहा हू। **...(व्यवधान)...**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: How much is the amount?

SHRI RAJNATH SINGH: Rs. 876 crores.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: For Corridors?

SHRI RAJNATH SINGH: In 1999-2000, for the NHAI...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: What is the allocation in the Budget for the current year, 2000-2001?

SHRI RAJNATH SINGH: Rs. 1,032 crores were given for the NHAI.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Minister, you are giving the figure for 1999-2000. I want to have the figure for 2000-2001!

SHRI RAJNATH SINGH: In 2000-2001, an amount of Rs. 2,010 crores has been allocated to the NHAI, for development of roads, under the National Highway Development Programme.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: What is the break-up of the figures for these two separate projects—Corridors and Golden Quadrilateral?

श्री राजनाथ सिंह: ब्रेक-अप की भी मैं जानकारी दे सकता हूं। यदि माननीय सभापति महोदय इजाज़त दें तो मैं यह जानकारी दे सकता हूं कि हमारे कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स इस समय इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत चल रहे हैं और उनकी कॉस्ट क्या है? ...(व्यवधान)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No no; if you don't have the figures, you say "I don't have."

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, वर्ष 2000-2001 के लिए मैंने बताया कि 2010 करोड़ रुपए का एलोकेशन एन०एच०ए०आई० के लिए हुआ है और एन०एच०ए०आई० इन 2010 करोड़ रुपयों की मदद से नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाली सड़कों का निर्माण करेगी।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I am asking for the break-up. Please understand the point. He gave me the figures for the Golden Quadrilateral and the Corridors project for the year 1999-2000. I wanted to have the figures for the year 2000-2001, for these two specific projects. If the Minister does not have the figures, he can always take time and place it on the Table of the House; no problem.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Sir, my question relates to the project itself. The Standing Committee on Tourism and Transport observed that in the plan of the Golden Quadrilateral and the Corridors, the coastal area has been completely left out and you all know that the coastal area has a great importance, from the point of view of both commercial and industrial production. Mangalore, Goa, Cochin and other important centres like Karwar have been left out. The Committee, I understand, recommended the road connectivity of the Golden Quadrilateral and the Corridors project with the major ports of the country. Has the Ministry taken into account this observation? If so, what are they going to do? Are they going to implement it? This is part (a) of my question.

Part (b) of my question, of course, does not relate to the Standing

Committee Report. It is a newspaper clipping from "The Indian Express". They observed last February that the NH Programme is running into a problem because the Department of Surface Transport is refusing to hand over some Kilometres of road to the NHRTP.

Now, they are saying that the NHAI is not equipped to begin the work on the project at the moment. Is that true? Or, is that not true? If it is true, are the State Governments being consulted or taken into confidence?

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवालाः सभापति महोदय, स्टेंडिंग कमेटी की कार्यवाही कांफिडेंशियल होती है जब तक उसकी रिपोर्ट सदन में नहीं रखी जाती है। क्या स्टेंडिंग कमेटी की कार्यवाही से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है?

MR. CHAIRMAN: Has the report been laid on the Table?

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: That I don't know.

MR. CHAIRMAN: Then, you should not ask questions on the basis of that.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Sir, there is the second part of my question regarding the NHAI running into trouble. It is not related to the Standing Committee Report. Anyway, my question remains, irrespective of the Standing Committee Report. The point is whether the connectivity of the coastal areas with the golden quadrilateral and the corridors is under consideration. This is (a) part of my question. Part (b) of my question is this. There is a newspaper report that the project is running into problems.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: You are repeating the same question.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: No, it is not a repetition. This first question is regarding connectivity. The second question is regarding the NHAI running into problems. Is it true that the Ministry of Surface Transport is refusing to hand over 7,000 kilometres to the National Highway Authority of India, on the ground that it is not presently competent enough? Is that true? If so, whether the States have been taken into confidence?

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहूंगा कि टॉस्क फोर्स ने बहुत विचार-विमर्श करके नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

को फाइनल किया है। इसलिए रि-एलाइंमेंट किसी प्रकार भी संभव नहीं है। जहां तक कोस्टल एरियाज को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की सड़क के साथ जोड़ने का प्रश्न है, मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे मेजर पोर्ट्स हैं उनको इन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली सड़कों के साथ जोड़ने की हमने व्यवस्था की है। ऐसी सड़कें लगभग एक हजार किलोमीटर की हैं जिन पर चार हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। माननीय सदस्या ने जो दूसरा प्रश्न किया है उसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो कुछ भी इन्होंने समाचारपत्रों में पढ़ा है वह सही नहीं है।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम के गलियारे में जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वह पूरे भारत को कवर कर रहा है किंतु भारत के बहुत से भाग खासकर मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्व क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जो नेग्लेक्टेड हैं। उनके बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं। अभी मंत्री जी ने पोर्ट्स के बारे में बताया है तो क्या मंत्री जी नार्थ-ईस्ट अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड की सड़कें इस गलियारे के साथ जोड़ेंगे? महोदय, मैं बिहार से आता हूं। हमारे घर की बगल से अगर गंगा पार करनी हो तो हमें करीब डेढ़ सौ किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। गंगा के उस पार मुंगेर है। अगर नेशनल हाईवे के साथ-साथ नेशनल ब्रिज भी बन जाए तो उसको बड़े-बड़े शहरों से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए मंत्री महोदय के पास क्या स्कीम हैं, कृपया बताने की कृपा करें?

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैंने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी है कि टॉस्क फोर्स ने बहुत विचार-विमर्श करके ही इस योजना को तैयार किया है। इसलिए फिलहाल किसी भी तरह का रि-एलाइंमेंट संभव नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो लोकेशन्स की चर्चा की है इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हमारे देश के जो अन्य नेशनल हाईवे की सड़कें हैं उनको कम से कम राइडिंग क्वालिटी की बना दें, उनको अप-ग्रेड कर दें। नौवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहेंगे कि इस देश का एक भी ऐसा प्वाइंट न बचे जहां से किसी भी नेशनल हाईवे पर पहुंचने में पचास किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़े। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने पूछा कि मध्य भारत का बहुत सारा भाग छूट गया है जो इस गोल्डन क्वाड्रीलेट्रल एंड दि कॉरीडोर स्कीम के अंतर्गत नहीं आ पा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य भारत की काफी लंबी सड़क इस स्कीम के अंतर्गत कवर हो रही है। यदि माननीय सदस्य उसकी जानकारी चाहें तो मैं दे सकता हूं।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: नॉर्थ-ईस्ट का क्या हुआ?

SHRI J. CHITHARANJAN: Mr. Chairman, Sir, the hon, Minister said that various ports in the Western Coast will be connected to the

National Highway. But the demand is that there should be a West Coast Road, as a National Highway. It is not a question of realignment, but of a new National Highway connecting Mumbai with Cape Comorin through the West Coast. Because several major ports of the country are situated there; major tourists' centres are also there; and major industrial centres are also there. Therefore, that demand is a justifiable demand. I would like to know whether the hon. Minister will sympathetically consider the demand and take positive steps in this regard.

श्री राजनाथ सिंह: राज्य सरकारों द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार या हमारे मंत्रालय को प्राप्त होगा तो हम निश्चित रूप से उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

श्री रामदेव भंडारी: सभापति महोदय, बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग 57 में दरभंगा और फारबीसगंज के बीच एक मिसिंग लिंक है। यह इलाका भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है और काफी पिछड़ा इलाका है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने से बहुत बड़ी आबादी इससे लाभ उठाएगी और उस इलाके का सर्वांगीण विकास होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस समय सरकार उस पर क्या काम कर रही है? काफी परिश्रम के बाद मुझ सहित उस क्षेत्र के सभी सांसदों ने बार-बार रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को दिया उस के बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। अद्यतन स्थिति क्या है? दरभंगा और फारबीसगंज के बीच जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनने वाला है उसे फेज वाइज बनाने का क्या कार्यक्रम है? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इसके स्पेसिफिक स्ट्रेच के बारे में जानकारी चाही है। यदि वे लिखित रूप में इसकी जानकारी चाहेंगे तो यह मैं उन्हें दे दूंगा। जहां तक इस सड़क के बन जाने से बिहार के सर्वांगीण विकास का प्रश्न है ..**(व्यवधान)**

श्री रामदेव भंडारी: बिहार ही नहीं यू०पी० की भी यही स्थिति है। मैं उस क्षेत्र के विकास की बात कर रहा हूं।

श्री राजनाथ सिंह: मुझे जो सूचना अभी मिली है उसके आधार पर दरभंगा से लेकर फारबीसगंज ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर का पार्ट है। इसमें फोर लेन सड़क बनेगी और यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़क होगी।

श्री रामदेव भंडारी: आप जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। मंत्री जी, ठाकुर साहब को भी ले चलिए। हम स्वागत की तैयार रखेंगे। आप देख लीजिए फिर आप जरूर बना देंगे।

श्री राजनाथ सिंह: माननीय सभापति, मैं बिहार से अनभिज्ञ नहीं हूं। बिहार से मेरा बहुत ही मधुर रिश्ता है। बिहार में मेरी ससुराल है इसलिए मैं बिहार को अच्छी तरह से जानता हूं

इसलिए केवल इस काम से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिहार की सड़कों से अच्छी तरह परिचित हूं।

श्री रामदेव भंडारी: आप उसकी लिखित जानकारी हमें भेज देंगे तो कृपा होगी।

†**श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक़:** ओनरेबल मिनिस्टर साहब ने कोमिशाहराहों रूट की तरक्की और नई कोमिशाहराह, जिसे उन्होंने टेक्नीकल नाम दिया, कॉरीडोर स्कीम, इसके बारे में जो वजाहत फरमाई है, उस सिलसिले में मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि नार्थ को साउथ से मिलाने के लिए इनके पास जो स्कीम है या यह बेहतर होता अगर साउथ से उस पर काम शुरू होने के साथ-साथ कश्मीर से भी काम शुरू हो जाता? इस तरह से दो तरफ उस पर काम शुरू होगा। एक तरफ ये जो सड़कें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब पाकिस्तान गए थे बस यात्रा से, तो किसी ने उनसे पूछा था कि बस से क्या होगा? उन्होंने कहा कि बस दिलों को जोड़ती है। अगर वाकई यह फलसफा दुरुस्त है तो मुझे लगता है कि इनको पूरे तौर से कश्मीर से भी यह सिलसिला शुरू करना चाहिए। जब राजीव गांधी वजीरे आजम थे, उन्होंने वहां आकर हमें यकीन दिलाया था कि हम जम्मू से श्रीनगर तक फोर लेन रोड बनायेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वह हो नहीं पाया। हमारा रास्ता, जैसा कि सभी लोगों को जो यहां मौजूद हैं, उनको मालूम है कि 6 महीने हमारा रास्ता बंद रहता है, हम सब से कट-ऑफ रहते हैं। इस चीज के पेशेनजर यह मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री आफ सरफेस ट्रांसपोर्ट इस सिलसिले में क्या खसूसी इंतजाम करेगी और जम्मू से श्रीनगर तक फोर लेन सड़क डेवलप करेगी? क्या श्रीनगर से भी इस कारीडोर स्कीम की शुरूआत हो सकती है, इसके बारे में मैं जानकारी चाहूंगा?

श्री राजनाथ सिंह: सभापति जी, नार्थ-साउथ-इस्ट-वेस्ट कारीडोर के अन्तर्गत आने वाली जो सड़क है उसके प्राइवेटाइजेशन के लिए स्टडी का काम इस समय चल रहा है और मैं समझता हूं कि सितम्बर अथवा अक्तूबर, 2000 के अंत तक प्राइवेटाइजेशन स्टडी का काम पूरा हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन स्टडी हो जाने के बाद हम यह असेस करते हैं कि कौन सी स्ट्रैच, कौन सी सड़क कमर्शियली वाइबल हैं। जो स्ट्रैच कमर्शियली वाइबल होती है, पहले हम उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराते हैं। महोदय, श्रीनगर के आसपास सड़क बनाने के लिए माननीय सदस्य ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि यह स्ट्रैच कमर्शियली वाइबल होगी। जहां तक मेरा विश्वास है कि पर्टिक्युलरली श्रीनगर तक यह वाइबल होगी या नहीं यह विचार का विषय है लेकिन जम्मू तक निश्चित रूप से यह कमर्शियली वाइबल होगी।

Monitoring of water table in Orissa

*603. SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the names of the districts of Orissa and the number of locations

†Transliteration of this speech in perisian Script is available in the Hindi version of the debate.